केंद्र में एक दल की सरकार आवश्

प्रो. राजेंद्र सिंह
(सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)

सप्ताह का इन्टरव्यू

जातिवादी राजनीति की पक्षधर हो गई है। इस स्थिति से क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है ?

उत्तर : दलित भी हिंदू समाज के अंग हैं। इसलिए उन्हें साथ लेकर चलना अनुचित नहीं है। सामाजिक स्तर पर हम दलितों के कहीं का निवारण करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं लेकिन यह प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर बहुत जटिल है एवं उसकी गति बहुत धीमी है। इस बीच अनेक दलित नेता राजनीति में बहुत सक्रिय हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी यद्यपि सभी दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, फिर भी उसमें १०-११ प्रतिशत दलित वोट हासिल करने की क्षमता है। उसके प्रभाव क्षेत्र में जाटव अधिक हैं। इसी प्रकार पिछड़ों में यादवों का वर्चस्व है लेकिन कोई एक यादव नेता सभी पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें भाजपा के प्रत्याशी अधिक जीतते रहे हैं। भाजपा को वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका नेतृत्व स्थापित नहीं हो पाया है इन वर्गों में। हमारा मानना है कि भाजपा का नेतृत्व स्थापित होने पर ऐसे नेताओं का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा जिनकी शक्ति कम है और आकांक्षाएं बहुत अधिक। इसीलिए जब हमसे पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी से समझौता करें तो आपको कैसे लगेगा, हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न : संघ की स्थापना के ७२ वर्ष बीत जाने पर भी हिंदू समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक एकता स्थापित क्यों नहीं हो पाई है ? क्या ऐसा नहीं लगता कि एकता स्थापित होने की बजाय बिखराव अधिक आया है ?

उत्तर : हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हमारा प्रयास एक ढंग से चल रहा है। राजनीति में जो लोग काम करते हैं, वे हमेशा तोड़ पैदा करते हैं। यदि तोड़ पैदा नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे। यह सच है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद बढ़ा है लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि हमारे देश में जो कई जातियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रांत हैं, इन सबके बीच अगर कोई एक वर्ग खड़ा है, तो यह संघ ही है। इसलिए हमें लगता है कि इनसे धीरे-धीरे संपर्क बढ़ने पर हम शेष लोगों के बीच भी पहुंच सकते हैं। वैसे यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभाजन के बाद भी हिंदुत्व का भाव जितना बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा। हिन्दुत्व का भाव सरदार पटेल की कारण भी बढ़ना चाहिए था, पर वह नहीं बढ़ा। आप जानते हैं कि जिन दिनों राम मंदिर का प्रश्न था, तब कितनी एकता दिखाई दे रही थी सारे हिंदू समाज में। तो हमारा ध्यान ऐसे मुद्दों पर है जिनसे हिंदुत्व की भावना बढ़े। अभी हमने हिंदी भाषा का प्रश्न उठाया हुआ है। राम मंदिर का प्रश्न उठाया हुआ है। स्वदेशी के साथ कुछ अन्य प्रश्न भी उठाए हुए हैं। हमारा प्रयत्न चल रहा है। पर आपकी यह बात ठीक है कि कभी-कभी राजनीतिक कारणों से कष्ट बढ़ जाते हैं। वैसे हमसे चिंतित और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न : आपने कुछ समय पहले दिल्ली में अपने एक भाषण में इस बात पर निराशा प्रकट की थी कि मूल्यों पर आधारित जो राजनीति होनी चाहिए थी, उसका बहुत ह्रास हो रहा है। निराशा का एक कारण यह भी है कि जो संघ से निकले हैं, या जो लोग भाजपा में हैं, चाहे राज्यों में हों या राष्ट्रीय स्तर पर, लोग उनसे अन्य दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अथवा कम्युनिस्टों की बजाय अधिक अपेक्षा रखते हैं लेकिन इधर राजनीतिज्ञों पर

जहां तक अनुशासन की बात है मैं यह बात मानता हूं कि इससे और अधिक अनुशासन होना चाहिए। यह कार्य समाज के प्रति अधिक समर्पण से ही संभव हो पाएगा। इसी दृष्टि से पिछले दिनों भी गोविंदाचार्य ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस तरह सलाह-मशविरा जारी है।

प्रश्न : बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मूल्यों का जो क्षय हो रहा है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को शायद नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विरोध करने पर भी एनरान समझौते पर भाजपा ने स्वीकृति प्रदान कर दी। कथनी और करनी के बीच यह अंतर क्या घातक नहीं है ?

उत्तर : जहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सवाल है, हम, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी उनका विरोध कर रहे हैं। यह बात अवश्य है कि जो शासन में आ जाते हैं, उन्हें कभी-कभी फास्ट ट्रैक की आवश्यकता होती है। फिर पुराने संबंध होते हैं। गठबंधन की विवशताएं होती हैं। लेकिन ऐसा मत मानिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति भाजपा का नरम रुख है। यदि विशेष टेक्नोलाजी का सवाल है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता ली जा सकती है। लेकिन आलू के चिप्स, पापड़ आदि बनाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छा जाएं, ऐसा हमें स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र में दो पार्टियों का गठबंधन है और ऐसी स्थिति में किसी एक पार्टी का दृष्टिकोण कारोबार से लागू नहीं किया जा सकता। परिस्थितियां जो भी हों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में जितने भी प्रयास करने होंगे, संघ और उसके अन्य हितैषी संगठन करेंगे।

प्रश्न : कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि देश में अब केवल गठबंधन की राजनीति अनिवार्य हो गई है लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी केंद्र में एकदलीय सरकार चाहते हैं। क्या आप भी इस विचार से सहमत हैं ?

उत्तर : हम यह मानते हैं कि केंद्र में एक दल की सरकार होने पर ही उसमें सही और कठोर निर्णय लेने की क्षमता आती है। जिसके पीछे पांच-दस लोग भी नहीं हैं, वह क्या निर्णय लेगा ? उसके सामने अनेक कठिनाइयां रहती हैं। अभी केंद्र में जो सरकार है, उसके १३ गति हैं। कभी कोई रुष्ट होता है, तो कभी कोई। हमारे सामने वेतन आयोग की सिफारिशों का उदाहरण है। ५२०० करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार पर डाल दिया गया है क्योंकि जिस भी यूनियन ने जो मांग की, वह सरकार को स्वीकार करनी पड़ी। प्रधानमंत्री साहस के साथ निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं— गठबंधन की सरकारों में।

प्रश्न : लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं। जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। इससे तो यही संदेश जाता है कि भाजपा भी गठबंधनात्मक राजनीति चलाना चाहती है।

उत्तर : गठबंधन की राजनीति के संबंध में हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। जहां तक राज्यों की विधानसभा का प्रश्न है, हम उन राज्यों में प्रभावी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल

को वापस उनके देश भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। कश्मीर की समस्या है। फारुख अब्दुल्ला उन सभी आतंकवादियों को १८०० रुपए प्रतिमाह के साथ नौकरी भी दे रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण के नाम पर केवल एक तमंचा सरकार को सौंपा है। वस्तुतः गठबंधन की राजनीति की चर्चा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शुरू की थी। कहीं भी ऐसी सरकार चली नहीं है।

देखिए, धीरे-धीरे जो स्पष्ट धारा की पार्टी है उसके साथ आज से अधिक लोग जुड़ेंगे और जब ऐसा होगा तब केंद्र में एकदलीय सरकार बनने में समय नहीं लगेगा। कांग्रेस को जब अनेक वर्गों का समर्थन प्राप्त था तब उसने इसकी चिंता नहीं की अब उसने भी विचार करना शुरू किया है तो उसकी विचारधारा में भी स्पष्टता आएगी। उसके साथ कौन-कौन जाता है यह देखना पड़ेगा। वैसे राजनीति के इस दौर में भी एक अच्छी बात यह हुई है कि कम्युनिस्टों की शक्ति कहीं बढ़ती दिखाई नहीं देती।

प्रश्न : वे तो पहली बार केंद्र में सत्ता में भागीदार हो गए हैं ?

उत्तर : यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सत्ता में शामिल होने पर भी उनका प्रभाव बढ़ा नहीं है।

प्रश्न : उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने से क्या यह संकेत नहीं मिलता कि भाजपा भी जातिगत राजनीति कर रही है, क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्ग को महत्व देने के नाम पर नेतृत्व की बागडोर सौंपी गई ?

उत्तर : थोड़ी-सी गलतफहमी रही है इस विषय को लेकर। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने यहां-वहां कोई एडजस्टमेंट चले ही कर लिया हो लेकिन हमारी नीति यह है कि नेतृत्व और शीर्ष पदों के स्तर पर हम जातिवाद को प्रश्रय कभी नहीं देंगे। देश की राजनीति में जातिवाद का विष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोला था, अपने स्वार्थ के लिए, देवीलाल और चौटाला को हटाने के लिए। यह विष अभी कुछ समय तकलीफ देगा लेकिन इसका भी अंत समीप आ गया है। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी का अन्य दलित संगठनों से जो तालमेल था, उसमें तेजी से बिखराव आया है। जहां तक उत्तर-प्रदेश का सवाल है, योग्यता और अनुभव के आधार पर कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया है।

प्रश्न : लंबे अर्से तक यह कहा जाता रहा है कि संघ और भाजपा में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। क्या अब इस छवि को बदलने के लिए अन्य जातियों के नेताओं को बड़ा दायित्व सौंपा जा रहा है ?

उत्तर : यह आरोप निराधार है। हम यह मानते हैं कि देश और समाज में जो सर्वोच्च पद हैं, उन पर

चित्र

कहना चाहिए कि यह व्यक्ति
योग्य है।

**प्रश्न : भविष्य में आप
किस बदलाव एवं विस्ता
रहे हैं ?**

उत्तर : सामान्यकाल में
गतिविधियां होनी चाहिए, वे
हमें यह आशंका होने लगी
के हाथ में है, सत्ता में रहने
आपस में ही झगड़ रहे हैं
देश को बेच न दें, बहुराष्ट्र
घुटने न टेक दें, पाकिस्तान
समझौता न कर दें। इस का
में है उन्हें हम बहुत तीव्र ग
कर रहे हैं और उनसे पूरे म

**प्रश्न : अयोध्या के बा
मथुरा की मुक्ति के मु
(कार्यसूची) में है ?**

उत्तर : देखिए, एजेंडा
ध्यान में यह आया
विचार किया कि संपू
जोड़ने वाली क्या-क
गो-रक्षा का काम चल
भी हिंदू समाज को जो
तब यह भी ध्यान में
(काशी और मथुरा)
क्योंकि उनके साथ
अयोध्या में, उनका क
नहीं है, यह मस्जिद त
बनी है। इस कारण अ

शुरू हुआ। फिर ताल
नींव का पत्थर रखा ग
एक कदम आगे बढ़
सरकार आई तो उसने
कर जमीन देने की
अयोध्या का मामला
बाकी के दोनों मामलों
नहीं था। जो बात अ
गई सारे देश में, वह
जन्मभूमि के माम
आवश्यकता नहीं प

आर्थिक दृष्टि से गो
की बात आई। इसमें ए
ये मुद्दे उठाने से गांधीजी
भक्त रहे थे सब लोग
विकास के नाम पर जुड़
पर जुड़ रहे हैं, स्वदेशी
यह ऐसा वर्ग था जो स
था और इस समय अ
कर रहा था, ये सब जु
मुद्दे उठाना आवश्यक ह
भी साथ आए और ह
हों। हम चाहते हैं कि